



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2010/अग्राहायण 23, 1932

No. 320]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2010/AGRAHAYANA 23, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान

(संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 7)

सं. 305-17/2010-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (v) तथा उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“इन विनियमों के विनियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 उस समय प्रवृत्त होंगे, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।”;

(ख) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 25 में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2010 (2007 का 4) के विनियम 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 उस समय तक प्रवृत्त रहेंगे, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।

एन. परमेश्वरन, मुख्य सलाहकार

[विज्ञापन III/4/142/10/असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 7) के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र का उपबंध करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 जारी किए थे। विनियमों के विनियम 13, 14, 15, 16 और 17, 15 दिसम्बर, 2010 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे, जबकि विनियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 और 22, 1 जनवरी, 2011 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे।

2. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सृजित किए जाने वाली वेबसाइट के सुरक्षा लेखापरीक्षा पहलुओं तथा इसमें अंतर्निहित अन्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह आवश्यक पाया है कि उक्त विनियमों के क्रियान्वयन के लिए तारीखों को पुनः निर्धारित किया जाए। तदनुसार, दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 के विनियम 1 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) तथा विनियम 25 के खण्ड (ख) और (ग) में संशोधन किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2010

The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Amendment) Regulations, 2010 (7 of 2010)

No. 305-17/2010-QoS.—In exercise of the powers conferred by Section 36 read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Regulations namely :—

1. (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations),—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“Regulation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 of these regulations shall come into force, as may be specified by the Authority, from time to time.”;

(b) clause (c) shall be deleted.

2. In regulation 25 of the principal regulations,—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“Regulation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007

(4 of 2007) shall remain in force till such time, as may be specified by the Authority, from time to time.”;

(b) clause (c) shall be deleted.

N. PARAMESWARAN, Principal Advisor

[ADVT III/4/142/10/Exty.]

Note 1 : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 305-17/2010-QoS dated 1st December, 2010.

Note 2 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of Telecom Commercial Communications Customer Preference (Amendment) Regulations, 2010 (7 of 2010).

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing unsolicited commercial communications. Regulation 13, 14, 15, 16 and 17 of the regulations were required to be implemented with effect from the 15th day of December, 2010, while regulation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 and 22 were required to be implemented with effect from the 1st day of January, 2011.

2. Having regard to the aspect of security audit of the website to be created for the purposes of these regulations and the other processes involved, the Telecom Regulatory Authority of India has found it necessary to re-determine the dates for implementation of the aforesaid regulations. Accordingly, clause (b) and clause (c) of sub-regulations (2) of regulation 1 and clause (b) and clause (c) of regulation 25 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 have been amended.